

‘मुख्यमंत्री कृषक मतिर योजना’

चर्चा में क्यों?

- 20 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन देने के लिये ‘मुख्यमंत्री कृषक मतिर योजना’ में हतिग्राहियों से फार्म भरवाने के कार्य का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में हुए राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने हरदा ज़िले के ग्राम जनिवानिया की नमति रनवे और भैरूदा सीहोर के प्रेमनारायण पंवार के आवेदन भरवाकर योजना में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन तत्काल आरंभ किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि योजना में 3 एचपी या अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन के लिये 200 मीटर तक की दूरी की 11 के.वी. लाइन के वसितार, वतिरण ट्रांसफार्मर की स्थापना और नमिन दाब लाइन केबल वसितार कार्य शामिल हैं।
- योजना में समस्त सामग्री सहित वसितार कार्य और इसका संधारण वदियुत वतिरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य का 50 प्रतिशत व्यय शासन द्वारा और 50 प्रतिशत कृषक या कृषक समूह द्वारा वहन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत ने ही मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में देश में अक्वल बनाया है। प्रदेश के शरबती गेहूँ, चन्निोर चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मलि रही है। प्रदेश में 2002-03 में खाद्यान्न उत्पादन 159 लाख मीटरकि टन था, जो अब बढ़कर 619 लाख मीटरकि टन हो गया है।
- राज्य सरकार ने किसानों के लिये 0% बयाज पर ऋण के साथ-साथ पर्याप्त बजिली और सचिाई की व्यवस्था की है। केन-बेतवा लकि परियोजना को स्वीकृति प्राप्त्त हो गई है, इससे प्रदेश में सचिाई का रकबा और बढ़ेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय प्रदेश में बजिली का कुल उत्पादन मात्र 2900 मेगावाट था। आज प्रदेश में 29 हजार मेगावाट से अधिक बजिली का उत्पादन हो रहा है। सचिाई क्षमता 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जसि 65 लाख हेक्टेयर से अधिक करना लक्ष्य है।
- योजना के प्रावधान**
 - अधोसंरचना वसितार कार्य एवं सामग्री की व्यवस्था वदियुत वतिरण कंपनी करेगी।
 - अधोसंरचना विकास के खर्च का 50% किसानों को देना पड़ेगा, 50 फीसदी खर्च राज्य सरकार/ बजिली वतिरण कंपनी देगी।
 - पंप कनेक्शन के लिये ज़रूरी लाइन, ट्रांसफार्मर आदि का मेंटेनेंस भी बजिली वतिरण कंपनी करेगी।
 - कृषकों के समूह यदि आवेदन करते हैं तो समूह के सदस्यों के द्वारा समानुपातिक रूप से खर्च उठाना पड़ेगा।
 - किसानों को केवल 50 प्रतिशत राशि भरनी पड़ेगी।
 - ट्रांसफार्मर एवं अन्य सामग्री की बेहतर गुणवत्ता से नरिबाध वदियुत, समस्त रख-रखाव संबंधी कार्य अब बजिली वतिरण कंपनी करेगी।
 - योजना लागू होने से 2 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी, प्रथम वर्ष में 10,000 किसानों को लाभ होगा।



PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/-chief-minister-krishak-mitra-yojana->

